तैयारी दो सेंटर ऑफ एक्सिलेंस से सस्ती और स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर होगा फोकस

ग्रीन हाइड्रोजन के स्टार्टअप्स को फंड करेगी सरकार

50 करोड़ रुपये तक की शत प्रतिशत सरकारी सहायता से हाई ऐंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा

AI Image

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में चल रहे स्टार्टअप्स को राज्य सरकार बढ़ावा देगी। राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए दो सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े स्टार्टअप्स को पांच साल तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन की लागत घटाकर उत्तर प्रदेश को देश की ग्रीन एनर्जी टेक्नॉलजी का प्रमुख केंद्र बनाया जाए।

योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दो सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग से जुड़ी तकनीक विकसित करना और लागत को न्यूनतम करना है। दोनों सेंटर देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। सरकार की ओर से इन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे अत्याधुनिक लैब और परीक्षण सुविधाएं विकसित की जा सकें।

राष्ट्रीय लक्ष्य में भूमिका निभा रहा उत्तर प्रदेश

वर्ष 2070 तक देश को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका भी निभा रहा है। गोरखपुर जिले में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा चुका है। अनुमान है कि इस प्लांट के माध्यम से 500 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। इसी सोच के साथ ग्रीन हाइड्रोजन नीति में स्टार्टअप्स के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन रखा गया है। उन्हें 5 साल तक, हर साल अधिकतम 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये स्टार्टअप्स किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के इनक्यूबेटर से जुड़े होने चाहिए। इससे जहां एक ओर युवाओं को शोध आधारित उद्यमिता का अवसर मिलेगा, वहीं उद्योग को नई तकनीक सुलभ होंगी।